

रक्षा अधगि्रहण परिषद

रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council- DAC) ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक हेतु 70,500 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिये 'बाय इंडियन-IDDM' (स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित) के तहत**आवश्यकतानुसार स्वीकृति (Acceptance** of Necessity- AoN) को मंज़ूरी दी।

अधिग्रहण प्रस्तावों की प्रमुख विशेषताएँ:

- भारतीय नौसेनाः
 - कुल प्रस्तावों में से <u>भारतीय नौसेना</u> के प्रस्तावों में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्वदेशी<mark>ब्रह्मोस</mark> करूज़ मिसाइल, शक्ति इलेकट्रॉनिक वारफेयर (EW) सिस्टम, युटलिटी हेलीकॉप्टर-मैरीटाइम शामिल हैं।
- वायु सेनाः
 - ॰ भारतीय वायु सेना के लिये लॉन्ग रेंज स्टैंड-ऑफ हथियारों को मंज़ूरी मिली है, जिसे <mark>SU-30 MKI</mark> विमान <mark>में ए</mark>कीकृत किया जाना है।
- सेना:
- साथ ही भारतीय सेना के लिये 155mm/52 कैलिबर एउवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) के साथ-साथ हाई मोबिलिटिं।
 और गन टोइंग व्हीकल्स की खरीद की जाएगी।
- हिदुस्तान एयरोनॉटिक्स:
 - DAC द्वारा की गई इस घोषणा का हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स एक बड़ा लाभार्थी है, क्योंकि यह भारतीय तटरक्षक केएंडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) MK-III की आपूर्ति करेगा। यह हेलीकाप्टर निरानी सेंसर का पैकेज़ ले जाने में सक्षम होगा जो भारतीय तटरक्षक बल के संचालन के लिय पूरी रात कार्य करने की और निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करेगा।
- मधयम गति के समृद्री डीज़ल इंजन:
 - मेक-। कैटेगरी के तहत मध्यम गति के समुद्री डीज़ल इंजन का निर्माण स्वदेश में किया जाएगा।

रक्षा अधिग्रहण परिषद:

- DAC रक्षा मंत्रालय में तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा भारतीय तटरक्षक हेतु नई नीतियों एवं पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिये सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
- रक्षा मंत्री परषिद का अध्यक्ष होता है।
- कारंगिल युद्ध (1999) के बाद वर्ष 2001 में 'राष्ट्रीय सुरक्<mark>षा प्रणा</mark>ली में सुधार'**पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया** गया था।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/defence-acquisition-council-1